



**VAJIRAO & REDDY INSTITUTE**

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050

+918988886060

[www.vajiraoinstitute.com](http://www.vajiraoinstitute.com)

[info@vajiraoinstitute.com](mailto:info@vajiraoinstitute.com)

# TODAY'S ANALYSIS

(आज का विश्लेषण)

(01 February 2025)

## Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

## Important News:

- बजट 2025-26 के मुख्य निष्कर्ष और बजट का देश की आर्थिक एवं राजनीतिक प्रणाली में महत्व
- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25: भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन और भविष्य को लेकर प्रमुख निष्कर्ष

## ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



## बजट 2025-26 के मुख्य निष्कर्ष और बजट का देश की आर्थिक एवं राजनीतिक प्रणाली में महत्व:

### परिचय:

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लोकसभा में बजट पेश किया है। यह



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है।

- वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई और बड़ी है। हमने पिछले 10 सालों में दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है।

### बजट 2025-26 की मुख्य घोषणाएं:

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा, हमारा फोकस 'ज्ञान (GYAN) यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति' पर है। इसके साथ ही स्वास्थ्य, मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग इंडिया, रोजगार और इनोवेशन पर हमारा ध्यान केंद्रित है। हमारा उद्देश्य विकसित भारत बनाने पर है।

#### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



## पाँच मुख्य उद्देश्यों पर ज़ोर:

- आर्थिक विकास को गति देना
- समावेशी विकास सुनिश्चित करना
- निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना
- घरेलू उपभोग को मजबूत करना
- भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की व्यय शक्ति को बढ़ाना

## संशोधित आयकर संरचना :

- केंद्रीय बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग के लिए करों को कम करने के लिए एक संशोधित आयकर संरचना पेश की गई। नई कर व्यवस्था पर्याप्त राहत प्रदान करेगी, जिससे यह करदाताओं के लिए अधिक आकर्षक बन जाएगी।
- सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि नई कर व्यवस्था के तहत 12,00,000 रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा।

## रक्षा व्यय के लिए 4.91 लाख करोड़ रुपये आवंटित:

- केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने रक्षा व्यय में 7.6% की वृद्धि की है, जिससे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल 4.91 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- रक्षा व्यय में यह वृद्धि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

### नाभिकीय स्वच्छ ऊर्जा बल:

- स्वच्छ ऊर्जा की को गति देने के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 2047 तक कम से कम 100 GW परमाणु ऊर्जा विकसित करना है।
- इसके अलावा, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के लिए समर्पित ₹20,000 करोड़ की अनुसंधान और विकास पहल शुरू की जाएगी, जिसका लक्ष्य 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी रूप से विकसित SMR को चालू करना है।

### 'पीएम धन धान्य कृषि योजना':

- वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत एक नई पहल 'पीएम धन धान्य कृषि योजना' पहल कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण पहुंच वाले 100 जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- इन उपायों से अनुमानित 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

### SC/ST महिला उद्यमियों के लिए नई योजना:

- पांच लाख SC/ST महिला उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसमें अगले पांच वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण देना शामिल होगा।



## **बजट 2025-26 के अन्य प्रमुख बिन्दु:**

- **अटल टिंकरिंग लैब:** 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 ऐसी लैब स्थापित की जाएँगी
- **चिकित्सा संस्थानों में 10,000 अतिरिक्त सीटें शामिल की जाएँगी; 5 वर्षों में 75,000 चिकित्सा सीटें बनाई जाएँगी**
- **किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड; ऋण सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख की गई**
- **MSME: ₹20 करोड़ तक के टर्म लोन दिए जाएँगे**
- **शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा**
- **भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा**
- **जन विश्वास विधेयक 2.0: 100 प्रावधानों को अपराधमुक्त करने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा**
- **वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा: 4.8%**
- **वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य: 4.4%**

## **आर्थिक एवं राजनीतिक प्रणाली में बजट का महत्व:**

- **भारत में सरकार बनाने वाले किसी भी राजनीतिक दल की समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए, किसी भी सरकार के लिए आर्थिक स्थिरता और विकास हासिल करने के लिए एक सुनियोजित बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है।**

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)





- इसमें समाज के वंचित वर्गों का उत्थान, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और बहुत कुछ शामिल है।

### कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन:

- प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में, विधायिका राष्ट्र के धन को नियंत्रित करती है।
- विधायी मंजूरी के बिना कार्यपालिका द्वारा कोई भी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता है। बजट प्रस्तावों पर मतदान से पहले संसद में व्यापक बहस होती है।

### संसाधन का उचित आवंटन:

- संसाधनों का उचित आवंटन बजटिंग में कमजोरी के क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें संबोधित करने के लिए रणनीतिक रूप से संसाधनों का आवंटन करना शामिल है। यह सरकारी बजट तैयार करने के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक है।
- सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि धन समाज के उन वर्गों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

### आर्थिक विकास सुनिश्चित करना:

- बजट सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में कराधान को विनियमित करने की अनुमति देता है। निवेश और व्यय किसी देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने वाले प्रमुख कारक हैं।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- कर छूट और सब्सिडी प्रदान करके, सरकार व्यक्तियों को बचत और निवेश पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। यह, बदले में, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है और देश के समग्र विकास में योगदान देता है।

### **व्यवसाय और व्यापार को बढ़ावा:**

- व्यवसाय और उद्योग जगत उत्सुकता से सरकारी बजट का इंतजार करते हैं क्योंकि यह विभिन्न क्षेत्रों के लिए संसाधनों के आवंटन का खुलासा करता है। यह जानकारी व्यवसाय मालिकों को अपनी नीतियों को तदनुसार समायोजित करने और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान करने में सक्षम बनाती है।
- बजट आर्थिक विकास के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करता है और व्यवसायों को सफलता की ओर ले जाता है।

### **आर्थिक असमानता को कम करना:**

- आर्थिक असमानता किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है।
- बजट के माध्यम से सरकार समाज के वंचित वर्गों के लिए सार्वजनिक और आर्थिक कल्याण नीतियां पेश करके इस मुद्दे का समाधान कर सकती है।



- इन असमानताओं को लक्षित करके, सरकार का लक्ष्य एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी अर्थव्यवस्था बनाना है।

### सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को समर्थन:

- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग रोजगार और राजस्व उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक सुनियोजित बजट सरकार को इन उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने और ऐसी नीतियां पेश करने में सक्षम बनाता है जो उनके विकास को सुविधाजनक बनाती हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निरंतर संचालन और सफलता को सुनिश्चित करता है।

#### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

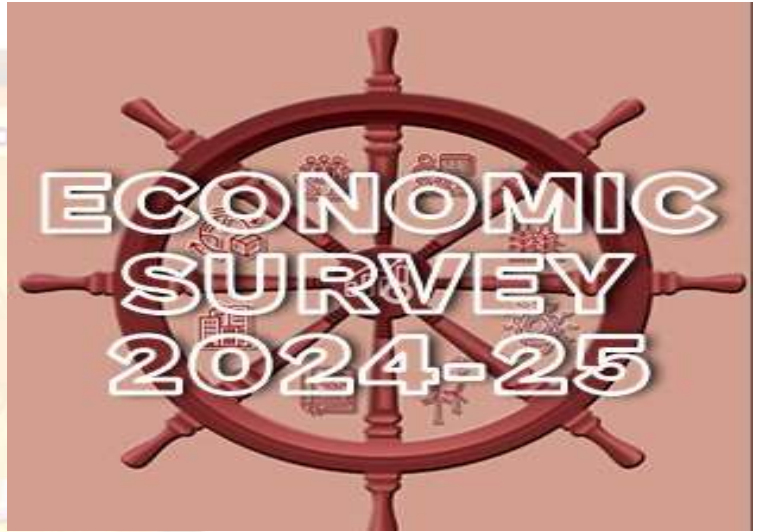




## आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25: भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन और भविष्य को लेकर प्रमुख निष्कर्ष

### परिचय:

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी को संसद में 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 चालू वित्त वर्ष के आर्थिक प्रदर्शन की



समीक्षा करता है और राष्ट्रीय चुनौतियों की पहचान करता है। यह भविष्य के सुधारों और विकास रणनीतियों का भी सुझाव देता है।

- इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है।

### अर्थव्यवस्था की स्थिति: तेजी से आगे बढ़ना

- वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो लगभग इसके दशकीय औसत के बराबर है। वित्त वर्ष 2024-25 में

ADDRESS:



वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (GVA) में भी 6.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

- उल्लेखनीय है कि घरेलू स्तर पर, निवेश में तेजी, उपभोक्ता विश्वास में सुधार और कॉर्पोरेट वेतन वृद्धि अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण मांग और स्थिर समष्टि आर्थिक स्थितियाँ वृद्धि की संभावना प्रदान करती हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधारों और विनियमन की आवश्यकता है।
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद में निजी अंतिम उपभोग व्यय का हिस्सा वित्त वर्ष 2023-24 में 60.3% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 61.8% होने का अनुमान है। यह वित्त वर्ष 2002-03 के बाद से सकल घरेलू उत्पाद का सबसे अधिक हिस्सा है।
- विकास के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक GDP वृद्धि 6.3 से 6.8 प्रतिशत के बीच बढ़ने की उम्मीद है।
- खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2023-24 में 5.4 प्रतिशत से घटकर अप्रैल-दिसंबर 2024 में 4.9 प्रतिशत हो गई है।
- मध्यम अवधि की विकास क्षमता को सुदृढ़ करने और भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर संरचनात्मक सुधारों और विनियमन पर जोर दिया गया है।

**ADDRESS:**

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 तक पूंजीगत व्यय (CAPEX) में लगातार सुधार हुआ है। आम चुनावों के बाद, जुलाई-नवंबर 2024 के दौरान CAPEX में सालाना आधार पर 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की सातवीं सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, जो इस क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को रेखांकित करता है।

### **वैश्विक अर्थव्यवस्था का संदर्भ:**

- अगले पांच वर्षों में 3.2 प्रतिशत वृद्धि के IMF अनुमान के मुकाबले वैश्विक अर्थव्यवस्था 2023 में औसतन 3.3 प्रतिशत बढ़ी।
- भू-राजनीतिक तनाव, चल रहे संघर्ष और वैश्विक व्यापार नीति जोखिम वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते रहते हैं।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में दो मुख्य चिंताओं को चिन्हित किया गया है। पहली चुनौती, व्यापक वैश्विक आर्थिक वातावरण प्रतिकूल और चुनौतीपूर्ण हो गया है, और वैश्विक व्यापार और निवेश "धीमा हो गया है"। सर्वेक्षण में कहा गया है, "वैश्विक व्यापार गतिशीलता हाल के वर्षों में काफी बदल गई है, वैश्वीकरण से बढ़ते व्यापार संरक्षणवाद की ओर बढ़ रही है, जिसके साथ अनिश्चितता भी बढ़ रही है"।

#### **ADDRESS:**



- दूसरी बड़ी चुनौती दुनिया की विनिर्माण महाशक्ति के रूप में चीन के प्रभुत्व से संबंधित है - वैश्विक उत्पादन का एक तिहाई हिस्सा चीन में होता है, और यह अकेले अगले 10 देशों की तुलना में अधिक वैश्विक उत्पादन का निर्माण करता है। हालांकि, वैश्विक आर्थिक विखंडन और उथल-पुथल के कारण, "वैश्वीकरण के युग में चीन को विनिर्माण आउटसोर्स करने की दुनिया की कार्यप्रणाली फिर से शुरू होने वाली है।

### कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन:

- वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र ने 3.5% की वृद्धि दर दर्ज की, जो पिछली चार तिमाहियों से सुधार दर्शाता है।
- **सुनिश्चित लाभकारी मूल्य:** सुनिश्चित लाभकारी मूल्य, संस्थागत ऋण तक बेहतर पहुँच और फसल विविधीकरण जैसे सरकारी हस्तक्षेपों ने निरंतर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **फूलों की खेती:** 100% निर्यात अभिविन्यास के साथ फूलों की खेती उद्योग एक उच्च प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र के रूप में उभरा है। यह कई पारंपरिक फसलों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक रिटर्न प्रदान करता है।

#### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- **उत्पादकता असमानताएँ:** जबकि भारत एक प्रमुख वैश्विक अनाज उत्पादक है, फसल की पैदावार अन्य प्रमुख उत्पादकों की तुलना में कम है, जो उत्पादकता में सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है।
- **विकास को बढ़ावा देने वाले संबद्ध क्षेत्र:** बागवानी, पशुधन और मत्स्य पालन जैसे उच्च मूल्य वाले क्षेत्र कृषि विकास में प्रमुख योगदानकर्ता हैं, जिसमें मत्स्य पालन सबसे अधिक CAGR दिखा रहा है।
- **अंतरराज्यीय भिन्नताएँ:** प्रमुख राज्यों में कृषि विकास में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, उसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु हैं।
- **बदलती आहार संबंधी प्राथमिकताएँ:** बढ़ती आय के कारण गैर-खाद्यान्नों, विशेष रूप से बागवानी उत्पादों, पशुधन और मत्स्य पालन की खपत बढ़ रही है, जिसके लिए मजबूत फसल कटाई-पश्चात प्रबंधन और विपणन अवसंरचना की आवश्यकता है।
- **सिंचाई कवरेज:** जबकि सिंचाई कवरेज में वृद्धि हुई है, कृषि भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वर्षा पर निर्भर है, जिससे यह मौसम के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है।





- **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन मौसम की परिवर्तनशीलता को बढ़ा रहा है, जिससे शुष्क अवधियों की आवृत्ति बढ़ रही है और तीव्र लघु वर्षा अवधियाँ हो रही हैं।

## **विकसित भारत के लिए आर्थिक हितधारकों के बीच 'विश्वास की कमी' को दूर करना:**

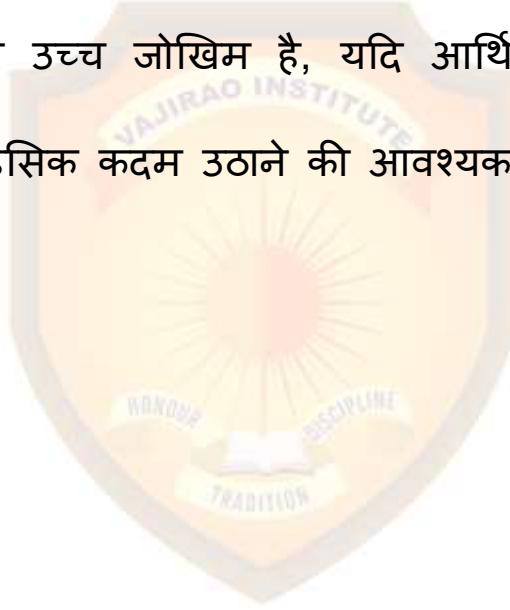
- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में देश में आर्थिक हितधारकों के बीच "विश्वास की कमी" के बारे में बहुत ही असामान्य स्पष्टता के साथ बात की गई है, जिसे दूर करने से विकसित भारत के लिए मार्ग प्रशस्त हो सकता है। विश्वास वास्तव में दो-तरफा रास्ता है। और शायद इसी विश्वास की कमी के कारण निजी निवेश चक्र मजबूत फर्म और बैंक बैलेंस शीट के "टेलविंड" के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाया है।
- सर्वेक्षण में कहा गया है कि "देश में विश्वास की कमी को खत्म करना अनिवार्य है और सरकारी एजेंसियों को इस संबंध में एजेंडा तय करना होगा"। साथ ही सर्वेक्षण का तर्क है कि अगले दो दशकों में उच्च विकास को बनाए रखने के लिए राजकोषीय या मौद्रिक प्रोत्साहन की नहीं, बल्कि "विनियमन प्रोत्साहन" की आवश्यकता होगी।

### **ADDRESS:**

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- उल्लेखनीय है कि इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। अत्यधिक विनियमन, आखिरकार, व्यवसाय के लिए लागत बढ़ाते हैं। लेकिन, विनियमन को हटाने की जिम्मेदारी, बड़े पैमाने पर, राज्य सरकारों के दरवाजे पर डाल दी गई है। सर्वेक्षण वास्तव में सही है जब वह कहता है कि "सामान्य रूप से व्यवसाय में आर्थिक विकास में ठहराव का उच्च जोखिम है, यदि आर्थिक ठहराव नहीं है"। ऐसे में वर्तमान समय में, साहसिक कदम उठाने की आवश्यकता है।



**ADDRESS:**

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)